पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का नागरिक समीक्षा सं०.21

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 519

==

1. कुमार गौरव सिंह, पुत्र कौशल किशोर सिंह, ग्राम का निवासी- शाहजहांपुर, थाना- शाहजहांपुर जिला पटना, रोल नंबर 21506672

2. अरविंद कुमार, पुत्र- गुलशन राय, गाँव के निवासी- पंचबीरिया, थाना- गरखा, जिला सारण, छपरा, रोल नंबर 21508143

3. सूर्य प्रकाश निराला, पुत्र- दिनेश प्रसाद, गांव के निवासी अब्दलपुर, थानाः- वारिसलीगंज, जिला नवादा, रोल नंबर 21502278

4. विकास कुमार, पुत्र उमेश प्रसाद निवासी- रक्सौल, थाना रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510979

5. अभिनंदन कुमार, पुत्र- शंभू प्रसाद, ग्राम के निवासी, थाना- लौरिया, जिला-मथियां, पश्चिम चंपारण, रोल नंबर 21503774

6. रजनीकांत सक्सेना, पुत्र सरोज कुमार गांव का निवासी गौरव नगर, थाना- एस.- परवालपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21505864

7. संजीव कुमार, पुत्र- राज कुमार साह, ग्राम के निवासी- मनियारपुर, थाना- बारिश नगर जिला- समस्तीपुर क्रम सं०- 21500802

8. राकेश कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, गाँव के निवासी- नवतोइला, जमालपुर रोड, थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर, रोल No.-21511817

9. श्याम बाबू कुमार, पुत्र-राजेंद्र प्रसाद, गाँव के निवासी-मुशसनिया, थाना-सोनवर्षा, जिला-सीतामढ़ी, रोल नंबर-21511662

10. नितीश कुमार, पुत्र- ज्ञान चंद भगत, गाँव के निवासी-परवता, थाना-परवता, जिला-खगड़िया, रोल नंबर-2150914

11. सुधीर कुमार, पुत्र- साधुशरण प्रसाद, ग्राम के निवासी-समाबाद, थाना-रहुई, जिला-नालंदा, रोल नंबर 21510431

.............अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष।

3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

4. शशि भूषण सिंह, पुत्र- श्याम मोहन सिंह, गांव के निवासी- सकरी, थाना-कुदरा, जिला-कैमूर, भभुआ, रोल नंबर-21514540।

5. संतोष कुमार, पुत्र-कृष्णदेव प्रसाद, ग्राम के निवासी- पंसलवा, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, रोल नंबर-21511091।

6. चन्द्र किशोर कुमार, पुत्र- सुरेश मेहता, ग्राम के निवासी- रेपुर, थाना- ग्वालपारा, जिला- मधेपुरा, क्रम सं०-21514166

7. विजय शंकर कुमार, पुत्र-शिव नाथ यादव, गांव के निवासी-तेलकाथू, थाना-एम. एच. नगर, हसनपुरा, जिला-सिवान, रोल नंबर-21511298

8. बिहार राज्य।

9. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

10. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।

11. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==

साथ

2020 का नागरिक समीक्षा सं० 19

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 520

==

1. नवनीत कुमार, स्वर्गीय पुत्र- भागवत प्रसाद, गांव के निवासी-रतनपुरा, थाना-इशलमपुर, जिला-नालंदा, रोल नंबर 21508391 ।

2. चंदन कुमार हीरा, पुत्र- लाल प्रसाद, मोहल्ला के निवासी-पूसा बाजार, थाना- पूसा, जिला समस्तीपुर, 2150-4788 ।

3. सुरेश कुमार, पुत्र- गणेश सिंह, ग्राम के निवासी-भूप भैरो, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, रोल नंबर 21503865।

4. विजय कुमार अशरफी रे, गांव के निवासी-खपुरा, के निवासी, डाक और थाना-खानपुर पाकरी, जिला-वैशाली, रोल नंबर 21511011।

5. बिपिन कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद, ग्राम के निवासी- खाखरा, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा, क्रम संः- 21512292

6. ललन कुमार, पुत्र- मुंद्रिका प्रसाद यादव के निवासी जयनगर बारी कवैगा, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय, क्रम सं०-21504710

7. शशि भुषण कुमार पुत्र- माधव प्रसाद यादव, ग्राम के निवास- राही जगतपुर, थाना- लक्ष्मीपुर लालचंद, जिला- मधेपुरा क्रम सं०-21502683

8. रविंदर कुमार पुत्र- वकील सिंह, गाँव के निवासी-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-रोहतास, रोल सं०.-21505435

9. संजय कुमार पुत्र-स्वर्गीय श्याम किशोर सिंह गाँव के निवासी-महथिन टोला, डाक और थाना-बालिगिरवन, जिला भोजपुर, रोल नंबर 21504660

10. नंदन सिंह, पुत्र जवाहर सिंह, गांव के निवासी-जमुराहा, थाना-रामगढ़, जिला कैमूर, रोल नंबर 21502502

11. दीपक कुमार, पुत्र सुशील कुमार यादव, गाँव के निवासी- कुशाहा, पी. ओ. कमलदह, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, अनुक्रमांक 21506290

12. अंशु कुमार आनंद, पुत्र- शिव नारायण सिंह, गांव के निवासी -रतनपुर, थाना- बरियारपुर, जिला मुंगेर, रोल नंबर 21503758

13. कुमार बीरेंद्र सिंह, पुत्र- नवल किशोर सिंह, गांव के निवासी-शेरपुर, पी. ओ. नेहुसा, थाना-हरनौत, जिला नालंदा, रोल नं०-.21508055।

14. उमेश प्रसाद सिंह पुत्र-स्वर्गीय भागवत सिंह, गांव के निवासी- बिशुनपुर बेदौलिया, थाना- जंदाहा, जिला-वैशाली, रोल सं०-21509314

15. धनंजय कुमार यादव, पुत्र-सुरेश यादव, निवासी- आजाद नगर रोड नंबर 3, थाना - कंकड़बाग, जिला पटना, रोल नंबर 21510343

................अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष।

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव।

4. हंसराज हंस, पुत्र- रामसेवक सिंह, गाँव के निवासी-सोमनाहा मठ, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर, रोल नंबर 21513082

5. मनोज कुमार, पुत्र- राम बदन चौधरी, ग्राम के निवासी- गमरियां, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, रोल नंबर 21512974

6. अमित कुमार, पुत्र- अशोक कुमार चक्रवर्ती, ग्राम के निवासी- रामदिहा, थाना- रहुई जिला- नालंदा क्रम सं०-21510622

7. मनोज कुमार अकेला, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद अकेला, ग्राम के निवासी नानंद, थाना- सिलाव, जिला नालंदा, रोल नंबर 21509910

8. अभिषेक कुमार, पुत्र- प्रदीप कुमार साह, ग्राम के निवासी- हफलागंज, डाकघर, थाना- सिरनिया, जिला- कटिहार, क्रम सं०- 21504108

9. अमित कुमार, पुत्र- स्वर्गीय भारत भूषण प्रसाद, ग्राम के निवासी- जलालपुर, थाना- सोहसराय, जिला नालंदा, रोल नंबर 21500334

10. आनंद कुमार, पुत्र- राम बदन प्रसाद, सेंट्रल केन्द्रीय राजस्व कॉलोनी, टाइप-III, निवास सं०- 49, थाना -दीघा, जिला पटना, रोल नंबर 21513795

11. बिपू कुमार प्रसाद, पुत्र- हरहंगी प्रसाद, ग्राम के निवासी- तिवारी छपरा, पी. ओ. थाना- भथवा, जिला- गोपालगंज, रोल नंबर 21500029

12. स्वर्ण किरण कुमार, पुत्र- नवल किशोर प्रसाद, ग्राम के निवासी- केवल बीघा, घंघ, डाकघर, थाना सैस्तापुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21501110

13. रवि कुमार, पुत्र- शंकर लाल साह, निवासी -दुर्गा स्थान कस्बा, थाना- कस्बा, जिला- पूर्णिया 21502813।

14. निशांत कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद केशरी, ग्राम के निवासी- मधुबानी बाजार, प्रेमा इलेक्ट्रिकल, थाना- के हाट, जिला-पूर्णिया, ईस्ट रोल नंबर 21510378

15. सुरेश गिरि पुत्र-स्वर्गीय बिंदेश्वरी गिरी, गाँव के निवासी- खुशारा निवासी, थाना- कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण, रोल नंबर 21510495

16. चंद्रशेखर कुमार पुत्र- भिखारी महतो, ग्राम के निवासी- राजवाड़ा बिरता, पी. ओ. मुशामिया, वाया- सोनबरसा, थाना- मुशरनिया, जिला- सीतामढ़ी

17. निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

18. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

19. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।

20. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

===

भारत का संविधान-अनुच्छेद 16-आरक्षण-50%-मेरिटोरियल आरक्षित उम्मीदवारों (एमआरसी) को उनकी पसंद के जिले में प्लेसमेंट/पोर्टिंग-रिट कोर्ट ने पोस्टिंग के लिए सिफारिश करने का निर्देश दिया-रिव्यू कोर्ट ने स्पष्ट किया।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के तहत विज्ञापित किया गया था कि उम्मीदवारों को विशिष्ट जिले को चुनने के लिए विकल्प दिए गए थे। सामान्य मेरिट सूची तैयार की गई थी जिसमें 17 मेरिट में उच्चतर आरक्षित उम्मीदवारों को सामान्य मेरिट में समायोजित किया गया था। हालाँकि, जहाँ तक जिलों के लिए किए गए विकल्पों का सवाल है, जब एक एमआरसी उम्मीदवार किसी जिले में आरक्षित रिक्ति के लिए हकदार था, जिसमें उसने एक विकल्प का प्रयोग किया था, तो उसे ऐसी आरक्षित रिक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इस एलपीए कोर्ट ने रितेश आर साह बनाम वाई.एल. यमुई; (1996) 3 एससीसी 253 और त्रिपुरारी शरण बनाम पर भरोसा किया। रामजी कुमार यादव, (2018) 2 एससीसी 656 पर भरोसा किया गया, और यूओआई बनाम रमेश राम (2010) 7 एससीसी 234 को लागू नहीं किया गया। खंडपीठ ने माना कि एमआरसी उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए जिले में स्थानांतरित करने से बनी 93 रिक्तियों को उन आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए, वे वैकल्पिक जिलों में अस्थिर हो जाएंगे, जहां उन्हें नियुक्त किया गया था।

अपील की अनुमति दी जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का नागरिक समीक्षा सं०.21

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 519

==

1. कुमार गौरव सिंह, पुत्र कौशल किशोर सिंह, ग्राम का निवासी- शाहजहांपुर, थाना- शाहजहांपुर जिला पटना, रोल नंबर 21506672

2. अरविंद कुमार, पुत्र- गुलशन राय, गाँव के निवासी- पंचबीरिया, थाना- गरखा, जिला सारण, छपरा, रोल नंबर 21508143

3. सूर्य प्रकाश निराला, पुत्र- दिनेश प्रसाद, गांव के निवासी अब्दलपुर, थानाः- वारिसलीगंज, जिला नवादा, रोल नंबर 21502278

4. विकास कुमार, पुत्र उमेश प्रसाद निवासी- रक्सौल, थाना रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510979

5. अभिनंदन कुमार, पुत्र- शंभू प्रसाद, ग्राम के निवासी, थाना- लौरिया, जिला-मथियां, पश्चिम चंपारण, रोल नंबर 21503774

6. रजनीकांत सक्सेना, पुत्र सरोज कुमार गांव का निवासी गौरव नगर, थाना- एस.- परवालपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21505864

7. संजीव कुमार, पुत्र- राज कुमार साह, ग्राम के निवासी- मनियारपुर, थाना- बारिश नगर जिला- समस्तीपुर क्रम सं०- 21500802

8. राकेश कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, गाँव के निवासी- नवतोइला, जमालपुर रोड, थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर, रोल No.-21511817

9. श्याम बाबू कुमार, पुत्र-राजेंद्र प्रसाद, गाँव के निवासी-मुशसनिया, थाना-सोनवर्षा, जिला-सीतामढ़ी, रोल नंबर-21511662

10. नितीश कुमार, पुत्र- ज्ञान चंद भगत, गाँव के निवासी-परवता, थाना-परवता, जिला-खगड़िया, रोल नंबर-2150914

11. सुधीर कुमार, पुत्र- साधुशरण प्रसाद, ग्राम के निवासी-समाबाद, थाना-रहुई, जिला-नालंदा, रोल नंबर 21510431

.............अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष।

3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

4. शशि भूषण सिंह, पुत्र- श्याम मोहन सिंह, गांव के निवासी- सकरी, थाना-कुदरा, जिला-कैमूर, भभुआ, रोल नंबर-21514540।

5. संतोष कुमार, पुत्र-कृष्णदेव प्रसाद, ग्राम के निवासी- पंसलवा, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, रोल नंबर-21511091।

6. चन्द्र किशोर कुमार, पुत्र- सुरेश मेहता, ग्राम के निवासी- रेपुर, थाना- ग्वालपारा, जिला- मधेपुरा, क्रम सं०-21514166

7. विजय शंकर कुमार, पुत्र-शिव नाथ यादव, गांव के निवासी-तेलकाथू, थाना-एम. एच. नगर, हसनपुरा, जिला-सिवान, रोल नंबर-21511298

8. बिहार राज्य।

9. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

10. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।

11. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==

साथ

2020 का नागरिक समीक्षा सं० 19

में

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 520

==

1. नवनीत कुमार, स्वर्गीय पुत्र- भागवत प्रसाद, गांव के निवासी-रतनपुरा, थाना-इशलमपुर, जिला-नालंदा, रोल नंबर 21508391 ।

2. चंदन कुमार हीरा, पुत्र- लाल प्रसाद, मोहल्ला के निवासी-पूसा बाजार, थाना- पूसा, जिला समस्तीपुर, 2150-4788 ।

3. सुरेश कुमार, पुत्र- गणेश सिंह, ग्राम के निवासी-भूप भैरो, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, रोल नंबर 21503865।

4. विजय कुमार अशरफी रे, गांव के निवासी-खपुरा, के निवासी, डाक और थाना-खानपुर पाकरी, जिला-वैशाली, रोल नंबर 21511011।

5. बिपिन कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद, ग्राम के निवासी- खाखरा, थाना- शेखपुरा, जिला- शेखपुरा, क्रम संः- 21512292

6. ललन कुमार, पुत्र- मुंद्रिका प्रसाद यादव के निवासी जयनगर बारी कवैगा, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय, क्रम सं०-21504710

7. शशि भुषण कुमार पुत्र- माधव प्रसाद यादव, ग्राम के निवास- राही जगतपुर, थाना- लक्ष्मीपुर लालचंद, जिला- मधेपुरा क्रम सं०-21502683

8. रविंदर कुमार पुत्र- वकील सिंह, गाँव के निवासी-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-रोहतास, रोल सं०.-21505435

9. संजय कुमार पुत्र-स्वर्गीय श्याम किशोर सिंह गाँव के निवासी-महथिन टोला, डाक और थाना-बालिगिरवन, जिला भोजपुर, रोल नंबर 21504660

10. नंदन सिंह, पुत्र जवाहर सिंह, गांव के निवासी-जमुराहा, थाना-रामगढ़, जिला कैमूर, रोल नंबर 21502502

11. दीपक कुमार, पुत्र सुशील कुमार यादव, गाँव के निवासी- कुशाहा, पी. ओ. कमलदह, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, अनुक्रमांक 21506290

12. अंशु कुमार आनंद, पुत्र- शिव नारायण सिंह, गांव के निवासी -रतनपुर, थाना- बरियारपुर, जिला मुंगेर, रोल नंबर 21503758

13. कुमार बीरेंद्र सिंह, पुत्र- नवल किशोर सिंह, गांव के निवासी-शेरपुर, पी. ओ. नेहुसा, थाना-हरनौत, जिला नालंदा, रोल नं०-.21508055।

14. उमेश प्रसाद सिंह पुत्र-स्वर्गीय भागवत सिंह, गांव के निवासी- बिशुनपुर बेदौलिया, थाना- जंदाहा, जिला-वैशाली, रोल सं०-21509314

15. धनंजय कुमार यादव, पुत्र-सुरेश यादव, निवासी- आजाद नगर रोड नंबर 3, थाना - कंकड़बाग, जिला पटना, रोल नंबर 21510343

................अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष।

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव।

4. हंसराज हंस, पुत्र- रामसेवक सिंह, गाँव के निवासी-सोमनाहा मठ, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर, रोल नंबर 21513082

5. मनोज कुमार, पुत्र- राम बदन चौधरी, ग्राम के निवासी- गमरियां, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, रोल नंबर 21512974

6. अमित कुमार, पुत्र- अशोक कुमार चक्रवर्ती, ग्राम के निवासी- रामदिहा, थाना- रहुई जिला- नालंदा क्रम सं०-21510622

7. मनोज कुमार अकेला, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद अकेला, ग्राम के निवासी नानंद, थाना- सिलाव, जिला नालंदा, रोल नंबर 21509910

8. अभिषेक कुमार, पुत्र- प्रदीप कुमार साह, ग्राम के निवासी- हफलागंज, डाकघर, थाना- सिरनिया, जिला- कटिहार, क्रम सं०- 21504108

9. अमित कुमार, पुत्र- स्वर्गीय भारत भूषण प्रसाद, ग्राम के निवासी- जलालपुर, थाना- सोहसराय, जिला नालंदा, रोल नंबर 21500334

10. आनंद कुमार, पुत्र- राम बदन प्रसाद, सेंट्रल केन्द्रीय राजस्व कॉलोनी, टाइप-III, निवास सं०- 49, थाना -दीघा, जिला पटना, रोल नंबर 21513795

11. बिपू कुमार प्रसाद, पुत्र- हरहंगी प्रसाद, ग्राम के निवासी- तिवारी छपरा, पी. ओ. थाना- भथवा, जिला- गोपालगंज, रोल नंबर 21500029

12. स्वर्ण किरण कुमार, पुत्र- नवल किशोर प्रसाद, ग्राम के निवासी- केवल बीघा, घंघ, डाकघर, थाना सैस्तापुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21501110

13. रवि कुमार, पुत्र- शंकर लाल साह, निवासी -दुर्गा स्थान कस्बा, थाना- कस्बा, जिला- पूर्णिया 21502813।

14. निशांत कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद केशरी, ग्राम के निवासी- मधुबानी बाजार, प्रेमा इलेक्ट्रिकल, थाना- के हाट, जिला-पूर्णिया, ईस्ट रोल नंबर 21510378

15. सुरेश गिरि पुत्र-स्वर्गीय बिंदेश्वरी गिरी, गाँव के निवासी- खुशारा निवासी, थाना- कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण, रोल नंबर 21510495

16. चंद्रशेखर कुमार पुत्र- भिखारी महतो, ग्राम के निवासी- राजवाड़ा बिरता, पी. ओ. मुशामिया, वाया- सोनबरसा, थाना- मुशरनिया, जिला- सीतामढ़ी

17. निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

18. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

19. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।

20. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

===

उपस्थिति:

(2023 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 519 में)

अपीलार्थी/गण के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता,
राज्य के लिए	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए. ए. जी.-13
बी. एस. एस. सी. के लिए	:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
		श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
		सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
		सुश्री सुष्मिता शर्मा, अधिवक्ता

(2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 520 में)

अपीलार्थी/गण के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के लिए अधिवक्ता	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए. ए. जी.-13
बी. एस. एस. सी. के लिए	:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
		श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
		सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
		सुश्री सुष्मिता शर्मा, अधिवक्ता

==

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

कैव निर्णय

(द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तिथि : 12-01-2024

आरक्षण का जटिल सवाल और इसे 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का जनादेश, ताकि योग्यता से समझौता न किया जा सके, इस विषय पर यहां विवाद उठाया गया। मामले के तथ्यों पर इस सिद्धांत को लागू करने के परिणामस्वरूप मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (संक्षिप्तता के लिए, 'एमआरसी') को उनकी पसंद के जिले दिए गए; केवल उनकी उच्च योग्यता के कारण सक्षम किया गया, जिससे आरक्षित उम्मीदवारों को परिणामी रिक्तियों में मेधावी सामान्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए हटा दिया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों, एक सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के मामले में और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, पर अपीलार्थी और उत्तरदाता द्वारा क्रमशः अपने प्रतिद्वंदी विवादों में समर्थन के लिए भरोसा किया गया था। अपीलार्थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संक्षिप्तता के लिए, 'बी. एस. एस. सी.') शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सेवा में नियुक्ति के रूप में अंतर का दावा करता है; जबकि उत्तरदाता-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्हें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के आरक्षण पदों पर होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया गया था, दावा करते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में लागू सिद्धांत पूरी तरह से यहां लागू होता है, हालांकि यह लोक सेवा के लिए एक नियुक्ति है।

3. निर्णयों की दो अलग-अलग पंक्तियाँ पर दोनों पक्षों द्वारा ***रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल (डॉ.), (1996) 3 एस. सी. सी. 253, त्रिपुरारी शरण बनाम रंजीत***

कुमार यादव, (2018) 2 एस. सी. सी. 656, डेगा वेंकट हर्ष वर्धन बनाम अकुला वेंटका हर्षवर्धन, (2019) 12 एस. सी. सी. 735 जो पर भरोसा किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और ***भारत संघ बनाम रमेश राम, (2010) 7 एस. सी. सी. 234*** से संबंधित है, ***आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य (2012) 13 एस. सी. सी. 516,*** में एक संविधान पीठ का निर्णय का पालन सिविल सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में किया।

4. निष्कासित किए गए 93 उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने अभिलेख पर कृषि निदेशक द्वारा लिखे गए एक पत्र जो सचिव 'बी. एस. एस. सी.' को संबंधित था, जिसमें 93 उम्मीदवार को जिलावार आबंटन एवं परिणामी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की मांग की गई थी। यह सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र पर आधारित था, (संक्षिप्तता के लिए, 'जी. ए. डी.') जिसमें पाया गया कि जब 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उनके वैकल्पिक जिलों में समायोजित किया जाता है, तो परिणामी रिक्ति आरक्षित उम्मीदवार को दी जानी चाहिए, जिसे वह पद मिलता जिसमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है, जो चिकित्सा शिक्षा में नियोजित प्रथा थी। कृषि विभाग को एक अलग रास्ता अपनाने के लिए फटकार लगाई गई और उसी सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस संचार को देखा; जिसने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण किया और रिक्त पदों के लिए सिफारिशें करने का निर्देश दिया। रिट याचिका में फैसले से एक अपील दायर की गई थी, जिसमें आवश्यक होने पर समीक्षा दायर करने का निर्देश था।

5. विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय से एक कानूनी राय के आधार पर, 'जी. ए. डी.' ने अपना रुख बदल दिया, जिसके कारण 'बी. एस. एस. सी.' ने एक समीक्षा दायर की, जिससे सिविल समीक्षा मामलों में विवादित आदेश दिया गया। समीक्षा इस आधार पर मांगी गई थी कि जब एम. आर. सी. उम्मीदवार अपनी समग्र योग्यता के आधार पर

अनारक्षित श्रेणी के लिए अनुशंसित है, लेकिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के भीतर योग्यता के आधार पर एक विकल्प पद या पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया है, तो आरक्षण रिक्ति को किए गए विकल्प के आधार पर समायोजित किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों को सामान्य योग्यता के लिए स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, एक एम. आर. सी. उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए एक विकल्प पर, यदि उसे आरक्षित श्रेणी के लिए अलग रखे गए एक विकल्प पद पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे आरक्षण पद पर 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार का कब्जा होता है। हालांकि, यदि 'एमआरसी' उम्मीदवार द्वारा इस तरह के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है और उसे केवल उसकी योग्यता के आधार पर तैनात किया जाता है, तो कम योग्यता वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार आरक्षण पद पर कब्जा करने का हकदार होगा। यह आरक्षण के अधिदेश के अनुरूप भी होगा जो एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जैसा कि संविधान पीठ द्वारा ***इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 का एस यू पी पी (3) एस. सी. सी. 217.***

6. समीक्षा में ***रमेश राम*** (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, बाद में 'जी. ए. डी.' द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बरकरार रखा गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि समीक्षा झूठ नहीं हो सकती है, विशेष रूप से समीक्षा क्षेत्राधिकार की रूपरेखा को देखते हुए, लेकिन चूंकि जो मांगा गया था वह केवल एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहले के आदेश में केवल उम्मीदवारों की अनुशंसा का निर्देश दिया गया था, जिसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि आरक्षित श्रेणी के उन 93 उम्मीदवारों की अनुशंसा की जानी थी, जिन्हें नियुक्ति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया था का पालन करना है। यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि अपील 93 निष्कासित आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मृगांक मौली ने मामले में उत्पन्न तथ्यों को इंगित करने के बाद तर्क दिया कि कृषि समन्वयक पद, जिस पद पर विषय चयन शुरू किया गया था, का विज्ञापन राज्यवार रिक्ति के आधार पर किया गया था। उम्मीदवारों को विशिष्ट जिलों को चुनने के लिए विकल्प दिए गए थे, क्योंकि रिक्तियों को प्रत्येक जिले से उत्पन्न होने के आधार पर अधिसूचित किया गया था। एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की गई थी जिसमें आरक्षित उम्मीदवार जो योग्यता में उच्च थे, उन्हें सामान्य योग्यता में ही समायोजित किया गया था। हालाँकि, जहाँ तक जिलों के लिए किए गए विकल्पों की बात है, जब एक एमआरसी उम्मीदवार एक जिले में आरक्षित रिक्ति का हकदार था, जिसमें उसने एक विकल्प का प्रयोग किया था, तो उसे ऐसे आरक्षित रिक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। ***रितेश आर. साह*** (ऊपर) और त्रिपुरारी शरण (ऊपर) से निकलते हुए कानून का विरोध करता है। ***रमेश राम*** (ऊपर) का कथन पूरी तरह से अलग परिस्थिति पर है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति पर इतना अंतर नहीं है, बल्कि रमेश राम (उपरोक्त) में लागू सिद्धांत के अनुसार विभिन्न सेवाओं के संबंध में स्थिति की कोई पहचान नहीं है, जिसमें नियुक्तियां की गई थीं।

8. ***त्रिपुरारी शरण*** (ऊपर) में स्थिति की एक पहचान थी क्योंकि एक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जा रहा था और विकल्प केवल उन संस्थानों में लागू किए जा रहे थे जिनमें इस तरह के प्रवेश किए जाते हैं। पहले मामले में, स्थिति में असमानता को देखते हुए, जहां तक विभिन्न सेवाओं का संबंध है, यह माना गया था कि एम. आर. सी. से आरक्षण पद में उच्च सेवा में आरक्षित रिक्ति की ओर बढ़ने के परिणामस्वरूप ऐसी आरक्षित रिक्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा। जबकि, जब स्थिति की पहचान होती है, तो एक पसंदीदा संस्थान का चयन केवल योग्यता के आधार पर 'एमआरसी' उम्मीदवार को एमआरसी में ही माना जा सकता है और किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अधिकार को दूसरे संस्थान में नियुक्त होने से वंचित नहीं कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में लागू

सिद्धांत सही आरक्षण सिद्धांत सुनिश्चित करता है और इससे किसी प्रकार से 50% नियम का उल्लंघन नहीं होता है। एम. आर. सी. उम्मीदवार को आरक्षित रिक्ति में स्थानांतरित करने से योग्यता पर कोई समझौता नहीं होता है और वह सामान्य योग्यता के आधार पर भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार बना रहता है, जबकि आरक्षित उम्मीदवार को किसी अन्य रिक्ति में नियुक्त किया जाएगा। यह केवल एम. आर. सी. उम्मीदवार की तुलना में कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार को पसंदीदा पोस्टिंग/संस्थान प्राप्त करने की अवैधता को दूर करता है। यह इंगित किया गया है कि अन्यथा सकारात्मक कार्रवाई की हताशा होगी।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें कृषि विभाग के संचार के माध्यम से अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कृषि विभाग और 'जी. ए. डी.' की संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर भी कहा गया था, जिसे अनुलग्नक-7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। त्रिपुरारी शरण (ऊपर) के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था। रिट याचिका का निपटान भी ऐसे निर्णय के आधार पर किया गया था जो केवल महाधिवक्ता के कार्यालय से दी गई कानूनी राय पर गिरा दिया गया था, जिसे अनुलग्नक-7 के साथ भी पेश किया गया है। यह इंगित किया गया है कि कानूनी राय गलत है।

10. शुरुआत में 'बी. एस. एस. सी.' की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती का तर्क है कि जहाँ तक कृषि समन्वयकों के पद का संबंध है, एक जिला संवर्ग है। उन्होंने कैडर नियमों और उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जिलों के चयन के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट विकल्प पर भी भरोसा किया जो कैडर नियमों से भी निकलता है। यह बताया गया है कि यदि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के कारण आरक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, तो आवश्यक रूप से, वे आरक्षण पदों पर कब्जा कर लेंगे और यदि उस रिक्ति में कोई अन्य आरक्षित उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है जिसके लिए 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार पात्र था, तो इसके परिणामस्वरूप

योग्यता से समझौता होगा और योग्यता रखने वाले सामान्य उम्मीदवार को योग्य नियुक्ति प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। यह इंदिरा साहनी (ऊपर) के एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित 50 प्रतिशत नियम का भी उल्लंघन करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति जैसे निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, उनमें अंतर बताया जाता है। वर्तमान मामले में, लोक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में निर्णय पूरी तरह से लागू होंगे और रमेश राम (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत से कोई विषयान्तर नहीं हो सकता है।

11. विज्ञापन दिनांक 29.04.2015, जो 2020 के सी. रिव. सं॰21 में अनुलग्नक - 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया कृषि निर्देशालय, बिहार पटना के वहत कृषि समन्वयकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आह्वान किया गया। अधिसूचित कुल रिक्तियां 4391 थीं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रत्येक आरक्षण श्रेणी के लिए पात्र रिक्तियों की संख्या भी निर्दिष्ट की गई थी। हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि वर्तमान मामले में उठाया गया एकमात्र मुद्दा बी. सी. उम्मीदवारों के संबंध में है। 4391 रिक्तियों में से 3507 को नियुक्त किया गया है। पदों पर लागू आरक्षण का एक सारणीकरण 2020 में सी.रिव. 21 की मंडिला 5 से देखा जा सकता है। हमें अन्य आरक्षण श्रेणियों के उम्मीदवारों को संदर्भित करने और केवल सामान्य और पिछड़े समुदाय के उम्मीदवारों के रूप में आंकड़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्रेणी में 2205 रिक्तियां थीं और 2169 उम्मीदवार विचाराधीन क्षेत्र में थे। अंतिम सिफारिश, जो कि जिलेवार थी, वह 1955 थी, जिसमें से 214 उम्मीदवार 'एमआरसी' उम्मीदवार थे। उनके द्वारा चुने गए पसंदीदा जिलों के आधार पर, उन्हें पसंदीदा जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें केवल ऐसे जिलों के आरक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित किया जा सकता था।

12. इस प्रकार चयनित जिलों में स्थानांतरित किए गए 214 एम. आर. सी. उम्मीदवारों में से 103 बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवार थे। बी. सी. श्रेणी में 10 रिक्तियां खाली रह गई थीं, जिनमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को विकल्पों के अभ्यास के अनुसार तैनात किया गया था। शेष 93 एम. आर. सी. उम्मीदवारों को भी उनके विकल्पों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों में तैनात किया गया था, जिन्हें आरक्षित पदों को भरने वाला माना गया था, इस प्रकार उक्त 93 पदों को सामान्य श्रेणी में स्वीकार कर लिया गया ताकि 50 प्रतिशत नियम का उल्लंघन न हो। परिणामस्वरूप, बी. सी. की आरक्षित श्रेणी के 93 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में आरक्षित रिक्तियों में 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के समायोजन के कारण नियुक्ति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया था, जिसमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों ने चुना था।

13. हम अपने सामने रखे गए निर्णयों की परीक्षा किए हैं। तथ्य इंगित करते हैं कि तथ्यों पर निर्णयों के दो समूह, पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में थे; लेकिन अंतर केवल उक्त तथ्यों पर नहीं है। अंतर्निहित सिद्धांत को ऐसे प्रवेशों या सेवाओं द्वारा प्रदान की गई स्थिति के आधार पर अलग किया जा सकता है; क्या नियुक्तियों/प्रवेशों में स्थिति की पहचान है या सेवाओं या पाठ्यक्रमों में असमानता है जिसमें नियुक्तियां और प्रवेश किए जाते हैं। जब 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उनके विकल्पों के आधार पर आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाता है, कौन से विकल्प उस सेवा की स्थिति को भौतिक रूप से नहीं बदलते हैं जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है; उन्हें आरक्षण रिक्तियों पर कब्जा करने वाला नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार आरक्षण श्रेणी में कम योग्य उम्मीदवारों को ऐसे एमआरसी उम्मीदवार द्वारा खाली किए गए पद पर कब्जा करने से वंचित कर दिया जाता है। हालांकि, जब स्थिति में असमानता होती है, तो अनिवार्य रूप से आरक्षित रिक्ति में भर्ती या नियुक्त 'एमआरसी' उम्मीदवार को आरक्षण उम्मीदवार माना जाएगा, इस प्रकार आरक्षण श्रेणी में कम मेधावी उम्मीदवार को

हटा दिया जाएगा और परिणामी रिक्ति के लिए सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा।

14. हमारी राय में, यह वह अंतर है जो हमारे सामने रखे गए उद्धृत निर्णयों से उत्पन्न होता है। रितेश आर. साह (ऊपर) एक ऐसा मामला था जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या एक एमआरसी उम्मीदवार, जिसे उसकी पसंद के कॉलेज में आरक्षित रिक्ति में समायोजित किया जाता है, को आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ गिना जाना चाहिए या उसे सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी उम्मीदवार को अपनी योग्यता के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिया जाता है तो इस तरह के प्रवेश को आरक्षण कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिए। यह निर्णय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संदर्भ में दिया गया था और इस सिद्धांत को कंडिका 17 में कहा गया था, जिसका ***रमेश राम*** (ऊपर) में निकाला गया हिस्सा इस प्रकार हैः-

> *"17. ... उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि एक छात्र जो योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है, हालांकि वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, उसे आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ प्रवेश नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही प्रावधान इस तरह से किए जाने चाहिए कि यह ऐसे उम्मीदवार के लिए नुकसानदेह न हो और उसे अन्य कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में न रखा जाए। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है यदि आरक्षित श्रेणी के*

उम्मीदवारों में से उम्मीदवारों का पता लगाने के बाद जो अन्यथा खुली योग्यता सूची में आते हैं और फिर विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए उनका विकल्प पूछते हैं जिन्हें आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है और उसके बाद कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें उन कॉलेजों में सीटें आवंटित की जानी चाहिए जहां सीटें उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जबकि अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां आरक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया माना जाएगा, न कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में।"

15. उपरोक्त भाग को निकालने के बाद, रमेश राम (ऊपर) ने पैराग्राफ-32 में ऐसा कहाः-

"32. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने और यूपीएससी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है क्योंकि बाद की परीक्षा विभिन्न दीवानी सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। पहले मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ मिलता है। हालांकि, बाद के मामले में सफल

उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभों में भिन्नताएं हैं क्योंकि वे अपनी पसंद की सेवा को सुरक्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश उम्मीदवार प्राथमिकताओं के लिए पूछे जाने पर पहली तीन सेवाओं [यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.), भारतीय विदेश सेवा (आई. एफ. एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.)] में से कम से कम एक का विकल्प चुनते हैं। अधिकांश उम्मीदवार पहले विकल्प के रूप में आई. ए. एस. को पसंद करते हैं। इस संबंध में, एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो सामान्य सूची के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसे सामान्य श्रेणी में रिक्तियों के मुकाबले निचली सेवा में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि अगर उसने अपने आरक्षित श्रेणी के दर्जे का लाभ उठाया होता, तो उसे उच्च वरीयता की सेवा मिलती। इस तरह की विसंगति को रोकने के स्पष्ट इरादे के साथ, नियम 16 (2) में प्रावधान है कि एक एमआरसी उम्मीदवार को सामान्य कोटा या संबंधित आरक्षित श्रेणी कोटा के बीच चयन करने की स्वतंत्रता है।"

16. ***रमेश राम*** (उपरोक्त) एक ऐसा मामला था जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में तीन अखिल भारतीय सेवाओं, पंद्रह समूह-ए सेवाओं और तीन समूह-बी सेवाओं के चयन को चुनौती दी गई थी। नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि आवंटन करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवार जो अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ अनुशासित है, को सरकार द्वारा आरक्षित

रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, यदि इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी पसंद के क्रम में उच्च पसंद की सेवा मिलती है। इस प्रकार, नियम 16 (2) ने किसी भी आरक्षित श्रेणी में मेधावी उम्मीदवार को उच्च वरीयता की सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाया ताकि उसे उसी आरक्षित श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सके। उक्त प्रपत्र में नियम को 04.12.2004 को संशोधित किया गया था, जिसके पहले इस तरह के समायोजन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कम योग्यता वाले उम्मीदवार को कम दर्जे की सेवा में चयन के लिए विचार करने से वंचित नहीं करेंगे; यदि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार का आरक्षित रिक्ति में समायोजन होता है।

17. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण [***रमेश राम*** (ऊपर) के पैराग्राफ-32] में देखा गया है कि ***रितेश आर. साह*** (ऊपर) से तथ्यों पर अंतर यह था कि पहले का मामला एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित था और बाद वाला विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए था। इस बात पर जोर दिया गया कि पहले मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ प्राप्त होता है जो एक योग्यता की ओर ले जाता है, जिससे चिकित्सा में अभ्यास करने में सक्षम होता है; जहां स्थिति की पहचान होती है और किया गया समायोजन केवल किसी विशेष कॉलेज में 'एमआरसी' उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की प्रकृति में होता है। यह विकल्प विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं; इलाके में अधिवास, गृहनगर से आसान पहुंच और यहां तक कि अधिक प्रतिष्ठित संस्थान प्राप्त करने के लिए; लेकिन सभी एमबीबीएस की समान योग्यता की ओर ले जाते हैं।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में एक अलग रास्ता अपनाते हुए विशेष रूप से ध्यान दिया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समूह-ए और समूह-बी पदों के लिए चयन में, उन सफल उम्मीदवारों को मिलने वाले

लाभों में असमानता है जो अपनी पसंद की सेवा सुरक्षित करने में अपने-आप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि एक एम. आर. सी. उम्मीदवार को उसकी योग्यता के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसके विकल्प के आधार पर उसे उस सेवा में आरक्षित रिक्ति में समायोजित किया जा सकता है। नियम इस तरह के समायोजन की अनुमति देता है लेकिन इसके परिणामस्वरूप 'एमआरसी' उम्मीदवार को आई. ए. एस. में आरक्षित रिक्ति में नियुक्त माना जाता है। अन्यथा, यदि योग्यता-आधारित आवंटन, प्रयोग किए गए सेवा के विकल्प के आधार पर नहीं किया जाता है, तो 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार को आई. पी. एस. में नियुक्त किया जाएगा, हालांकि उनका पहला विकल्प आई. ए. एस. था, जबकि एक अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्होंने समान विकल्प बनाया था, उन्हें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार की तुलना में कम योग्यता होने के बावजूद, आई. ए. एस. में आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए सक्षम किया जाएगा। इस तरह की विसंगति और अनावश्यक को ईर्ष्या दूर करने के लिए, विशेष रूप से अलग-अलग लाभ और अलग स्थिति वाली विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में, नियम इस तरह से बनाया गया था, ताकि एक आरक्षित रिक्ति में समायोजन किया जा सके; एक एमआरसी उम्मीदवार, एक उच्च या बेहतर सेवा में, जिसे आरक्षित श्रेणी में से एक माना जाता है। नियुक्ति की स्थिति में असमानता और किसी विशेष सेवा में बाद में अवशोषण के प्रक्षेपण पर उपरोक्त नियम बनाया गया था।

19. ***रमेश राम*** (ऊपर) के पैराग्राफ-35 में ऐसा माना गया थाः-

> “35. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दो चरणों में सी. एस. ई. परिणाम घोषित करने के औचित्य पर सवाल उठाया कि भले ही एम. आर. सी. उम्मीदवारों को उच्च वरीयता की सेवा दी जाए, उन्हें निम्न श्रेणी के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बाहर

> नहीं करना चाहिए। हालांकि, नियम 16 (2) की व्याख्या अलग तरीके से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसे एमआरसी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। एम. आर. सी. उम्मीदवार आवेदन के समय एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के रूप में अपनी स्थिति का संकेत देते हैं, आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में परीक्षा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी शुरू करते हैं। सामान्य योग्यता मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के बाद, उनके पास आरक्षित श्रेणी से बाहर निकलने और सामान्य पद पर कब्जा करने का अतिरिक्त विकल्प होता है। हालाँकि, जहाँ वे आरक्षित सूची में एक बेहतर पद प्राप्त करने में सक्षम हैं, सामान्य सूची में उनकी नियुक्ति उन्हें उससे वंचित नहीं करेगी। इस संबंध में, नियम 16 (2) में निर्दिष्ट समायोजन, वास्तव में, एम. आर. सी. की स्थिति में सामान्य से आरक्षित में किसी भी परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। इसके विपरीत, यह एम. आर. सी. उम्मीदवार के आरक्षित दर्जे की पुष्टि है। एम. आर. सी. उम्मीदवारों की इस आरक्षित स्थिति की रक्षा के लिए नियम 16 (2) मौजूद है।

20. यह सच है कि ***देग वेंकट हर्ष वर्धन और त्रिपुरारी शरण*** (दोनों ऊपर) फिर से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में थे हालांकि, हमें ***त्रिपुरारी शरण*** (ऊपर) में कंडिला-16 पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जहां अदालत ने विशेष रूप से ***रमेश राम*** (ऊपर) का उल्लेख किया है, जिसमें ***रितेश आर. साह*** (ऊपर) का एक स्पष्ट रूप से विपरीत निर्णय आया था। पीजी उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति और यूपीएससी उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के बीच अंतर बताया गया था। यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित था- "जबकि स्नातकोत्तर प्रवेश में, परिणाम सभी उम्मीदवारों को रैंक (यानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश) की परवाह किए बिना समान लाभ प्रदान करेंगे, यूपीएससी चयन में परिणाम अलग-

अलग रैंक धारकों को अलग-अलग लाभ देते हैं, क्योंकि सेवाओं का आवंटन रैंक (सिक) आधार पर होता है-विद्वान न्यायाधीशों ने भी पैराग्राफ-17 में ऐसा कहाः-

> “17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहां तक एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संबंध है, संविधान पीठ ने *रितेश आर. साह [रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल,* (1996) 3 एस. सी. सी. 253] को वस्तुतः लेकिन निहित रूप से मंजूरी दे दी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रमेश राम (*भारत संघ बनाम रमेश राम* (2010) 7 एस. सी. सी. 234:(2010) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 412] में निर्धारित किए गए सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित मामला है और जबकि रमेश राम [*भारत संघ बनाम रमेश राम,* (2010) 7 एससीसी 234: (2010) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 412] यू. पी. एस. सी. परीक्षा के माध्यम से सेवाओं के लिए पदों के चयन से संबंधित है।

21. ***आलोक कुमार पंडित*** (ऊपर) फिर से विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए एक चयन और नियुक्ति थी, जो यू. पी. एस. सी. द्वारा की गई नियुक्ति के समान है, जो ***रमेश राम*** (ऊपर) में विचार का विषय था।

22. यह उपरोक्त संदर्भ में है और सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट अंतर है न कि प्रवेश और नियुक्तियों के बीच अंतर पर, कि तत्काल मामले पर विचार किया जाना है।

23. तत्काल चयन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के तहत कृषि समन्वयक के पद के लिए था। विज्ञापन की एक प्रति सिविल समीक्षा मामलों में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत की जाती है जिनसे अपीलें उद्भूत होती हैं। बार में एक अनुवादित प्रति भी प्रस्तुत की

गई थी। विज्ञापन इस तरह के आरक्षण के हकदार विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्र रिक्तियों की संख्या और आरक्षण कोटा को इंगित करता है। विभिन्न जिलों में रिक्तियों का विवरण देते हुए, विज्ञापन प्रत्येक जिले में कुल स्वीकृत पदों को इंगित करता है जिनमें से आरक्षण कोटा और सामान्य कोटा को अलग किया गया था और अलग से दिखाया गया था। यह वह संदर्भ है जिसमें उम्मीदवार को 38 जिलों के संबंध में अपना विकल्प देना आवश्यक था। विज्ञापन में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि जो उम्मीदवार अपना विकल्प नहीं देंगे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जिला आवंटित किया जाएगा। इसलिए, जैसा कि रमेश राम (ऊपर) में है, उन सेवाओं में लाभों में कोई असमानता नहीं है जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपयोग किया जाने वाला विकल्प सेवा के संबंध में भी नहीं है; जो वर्तमान मामले में केवल एक संवर्ग पद है, और विशेष रूप से जिले के आवंटन के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक पदों का संबंध है, कोई जिला संवर्ग नहीं है और विज्ञापन में दिए गए आरक्षण के तौर-तरीकों से यह संकेत नहीं मिलता है कि चयनित जिलों में 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पद में कोई समायोजन किया जा रहा है और इस प्रकार, कम योग्य आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार करने से वंचित किया जा रहा है।

24. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309; कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2014 के तहत लाए गए संवर्ग नियमों की भी आपूर्ति की गई है। कृषि समन्वयक को ऐसे कार्मिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रखंड स्तर से नीचे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देते हैं; जो इसे राज्य संवर्ग बनाता है। रिक्तियों का निर्धारण जिलेवार किया जाता है और नियम स्वयं ही योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है जो एक विकल्प का प्रयोग प्रदान करता है। जो स्पष्ट रूप से अविद्यमान है। वह नियम 16 (2) के समान एक नियम है, जिसे रमेश राम (उपरोक्त) के मामले में देखा गया था। वास्तव में,

इस तरह के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस पद पर नियुक्ति की जाती है, उसकी एक पहचान चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के समान होती है। जिला वार विकल्प नियुक्त व्यक्ति को उसके गृह जिले या उसके अधिवास जिले के पास के जिले में रहने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है।

25. योग्यता सूची तैयार की गई और आरक्षण पद में स्थान पाने के हकदार उम्मीदवारों की एक सूची भी तैयार की गई, और फिर विकल्पों पर विचार किया गया। उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को पहले अपने वैकल्पिक जिले के लिए माना जाएगा और यह उस संदर्भ में है कि 'एमआरसी' उम्मीदवार जिन्हें योग्यता के आधार पर कृषि समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें आरक्षित रिक्ति में उनके वैकल्पिक जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो उन्हें राज्य की सेवा में कोई अतिरिक्त लाभ या कथित उच्च दर्जा नहीं देता है। यह सुविधा का एक नियम है ताकि एक मेधावी उम्मीदवार को उसके/उसकी विकल्प का जिला मिल सके, बनिस्पत उसके जो स्थिति की भिन्नता के परिणामस्वरूप हो, जब एक मेधावी उम्मीदवार को उसके विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर अलग स्थिति वाली उच्च सेवा आवंटित की जाती है । यदि उस सेवा में स्थिति की पहचान की स्थिति में, जिसमें नियुक्ति की जाती है, आरक्षित रिक्ति को उसकी पसंद के जिले को आवंटित एमआरसी उम्मीदवार द्वारा भरा गया माना जाता है, तो यह आरक्षित श्रेणी से संबंधित 'एमआरसी' उम्मीदवार की योग्यता को समाप्त कर देगा। इसलिए, जब उस जिले के रूप में प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर एक काल्पनिक समायोजन किया जाता है, जहां तक नियुक्ति की जानी है, तो नियुक्ति का स्थानांतरण केवल 'एमआरसी' उम्मीदवार और कम योग्यता वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के खिलाफ होता है, जिस स्थिति में, कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार को 'एमआरसी' उम्मीदवार के स्थानांतरण द्वारा बनाई गई रिक्ति पर विचार करना होगा। उपरोक्त तर्क पर, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी

राय है कि ***रमेश राम*** (ऊपर) में सिद्धांत लागू नहीं होगा और ***रितेश आर.साह*** और ***त्रिपुरारी शरण*** (ऊपर दोनों) में स्पष्ट रूप से लागू होगा।

26. हमारा मानना है कि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उन जिलों में स्थानांतरित करके बनाई गई 93 रिक्तियां जिन्हें वे चुने थे को उन आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए, वे उन वैकल्पिक जिलों में अस्थिर होंगे जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। यद्यपि अनुलग्नक-7 में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रारंभिक राय और महाधिवक्ता की राय का संदर्भ दिया गया था, हमारा विचार है कि यह इसमें उत्तेजित मुद्दे के निर्णय को विनियमित नहीं करता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा भी नियंत्रित होता है। हमारी व्याख्या विभाग और विद्वान महाधिवक्ता की व्याख्या पर हावी होगी।

27. अपीलों को उपरोक्त निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है जिससे पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करनी पड़ती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायमूर्ति मैं सहमत हूँ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

आदित्य/सुजीत/अनुष्का

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।